



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 —उप-खंड (ii)
PART II—Section 3 —Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122]
No. 122]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 1997/फाल्गुन 7, 1918
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 1997/PHALGUNA 7, 1918

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1997

का० आ० 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 43क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 251(अ), तारीख 30 मार्च, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, —

(1) खंड 1.2 के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तुक यह भी कि बहु-एकक परियोजना के मामले में प्रगतिशील एककों के वाणिज्यिक प्रचालन के समय प्राधिकरण द्वारा अपनी तकनीकी-आर्थिक निकासी में यथा विनिर्दिष्ट पूंजी लागत पर भी टैरिफ के नियतन के लिए विचार किया जाएगा। किन्तु दूसरे या पश्चात्पूर्ती एककों के नियत तारीख से प्रवर्तन में विलम्ब होने की दशा में, टैरिफ के प्रयोजन के लिए विलम्ब अवधि के लिए परियोजना लागत को, एककों के सामानुपातिक आबंटन के अनुपात में भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि परियोजना की पूंजी लागत में, विदेशी मुद्रा दर में फेरफार या विधि में परिवर्तन के कारण जिसे सक्षम सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, तकनीकी-आर्थिक निकासी में अनुमोदित लागत की तुलना में कोई वृद्धि होती है तो परियोजना विकासकर्ता, किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अनधिक, प्राधिकरण से पूंजीलागत के मध्यावधि पुनरीक्षण का प्रस्ताव कर सकता है।”

(2) खंड 1.5 में,

(क) पैरा (ग) में,

(i) “प्रचालन और अनुरक्षण व्यय” शब्दों के स्थान पर “प्रचालन और अनुरक्षण व्यय जिसमें बीमा सम्मिलित है” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) “टिप्पण” के स्थान पर निम्नलिखित “टिप्पण” रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“टिप्पण—1: प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष में प्रचालन और अनुरक्षण इसमें पहले वर्ष के लिए 2.5 प्रतिशत के आधार पर संगणित बीमा भी सम्मिलित है, पर व्यय भारित कीमत सूचकांक के आधार पर बोर्ड और उत्पादक कंपनी के बीच परस्पर करार पाए गए आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा। अनुकल्पतः, पहले वर्ष के लिए 2 प्रतिशत के आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष में भारित कीमत सूचकांक के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा, परन्तु प्रथम वर्ष के लिए बीमा पर वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम बीमा व्यय को पश्चातवर्ती वर्ष में बढ़ाया नहीं जाएगा।

टिप्पण—2 : बहु एकक परियोजना के मामले में टैरिफ के प्रयोजन के लिए प्रत्येक एकक से संबंधित प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, प्रत्येक एकक की क्षमता के अनुपात से संगणित पूंजी व्यय की ऊपर दी गई प्रतिशतता के आधार पर न कि तकनीकी-आर्थिक निकासी में पूंजी व्यय के आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा। यह वृद्धि एककों के प्रवर्तन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी;”

(ख) पैरा (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु विद्युत के कारबार में आय पर कर, वार्षिक नियत प्रभार के संघटक के रूप में अधिकतम सीमा गठित करेगा किन्तु बोर्ड, प्रोत्साहन से संबंधित आय पर कर को अनिवार्य रूप से टैरिफ में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं करेंगे और आय पर कर की बाबत जो 6000 घंटे (किलोवाट) वर्ष के उत्पादन स्तर से अधिक के मामले में इस आय पर कर की कटौती मानने के लिए बातचीत करेंगे;

(ग) पैरा (च) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

(च) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज में निम्नलिखित होंगे :—

- (i) मापक संयंत्र भार कारक के आधार पर संगणित एक मास के लिए ईंधन लागत और वास्तविक रूप से अनुरक्षित युक्तियुक्त ईंधन स्टॉक, गर्तमुख केन्द्रों के लिए पन्द्रह दिन तक और गैर-गर्तमुख केन्द्रों के लिए तीस दिन तक सीमित होंगी;
- (ii) मापक संयंत्र भार कारक के आधार पर द्वितीयक, ईंधन तेल का साठ दिन का स्टॉक;
- (iii) एक मास के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय (रोकड़);
- (iv) पूंजी लागत के अधिकतम एक प्रतिशत के अधीन रहते हुए वास्तविक अनुरक्षण पुर्जों, किन्तु पहले से पूंजीगत आरम्भिक पुर्जों के 115 भाग के मूल्य के कम करने के पश्चात् 1 वर्ष की आवश्यकता से अधिक के न हों; और
- (v) मापक संयंत्र भार कारक के आधार पर संगणित विद्युत के विक्रय के लिए दो मास की औसत दर पर बिलों के समतुल्य प्राप्ति;”

(3) खंड 1.6 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“1.6 सम्पूर्ण नियत प्रभार, 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष (स्थिरीकरण) अवधि के दौरान 4500 घं० (कि० वा०) वर्ष के उत्पादन स्तर पर वसूल किए जाएंगे। 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष के उत्पादन स्तर से कम नियत प्रभारों का संदाय अनुपातिक आधार पर किया जाएगा और 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष से ऊपर के स्तर के उत्पादन के लिए नियत प्रभारों का कोई संदाय नहीं होगा। 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष के ऊपर के उत्पादन के लिए, संदेय अतिरिक्त प्रोत्साहन, 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष के मापक स्तर से ऊपर संयंत्र भार कारक के प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि के लिए समादत्त और प्रतिश्रुति पूंजी के 0.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उत्पादन के स्तर की संगणना करते समय, उत्पादन करने की सीमा जिसके लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों अथवा राज्य उद्धारण प्रेषण केन्द्र द्वारा आदेश किया गया हो, उत्पादन प्राप्ति के रूप में संगणित की जाएगी। नियत प्रभारों का संदाय संबंधित बोर्डों और अन्य व्यक्ति द्वारा ली गई विद्युत के अनुपात में मासिक आधार पर किया जाएगा। वास्तविक के आधार पर आवश्यक समायोजन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा।

टिप्पण—1 : ऊपर वर्णित 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष के मापक स्तर से ऊपर प्रत्येक प्रतिशतता वृद्धि के लिए साधारण अंशों पर अतिरिक्त प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 0.7 होगी। उत्पादन कंपनियों और बोर्डों या अन्य विद्युत क्रेताओं को उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर उपर्युक्त निम्नतर अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए बातचीत करने और नियत करने की स्वतंत्रता होगी।

टिप्पण—2 : नैपथा आधारित तापीय संयंत्रों के लिए उत्पादन कम करने की सीमा को, जिनके लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों अथवा राज्य उद्धारण प्रेषण केन्द्र द्वारा आदेश दिया गया हो, 6000 घं० (कि० वा०) वर्ष के संयंत्र भार कारक से अधिक को प्रोत्साहन प्रयोजन के लिए प्राप्त उत्पादन के रूप में संगणित नहीं किया जाएगा।

टिप्पण—3 : डीजल ईजन उत्पादक एककों के लिए उत्पादन कम करने की सीमा को, जिसके लिए यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों अथवा राज्य उद्धारण प्रेषण केन्द्र द्वारा आदेश दिया गया हो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तत्समय अधिकथित संयंत्र भार कारक प्रचालन मापमानों को उसके उपान्तरणों, यदि कोई हैं, के अधीन रहते हुए, प्रोत्साहन प्रयोजन के लिए प्राप्त उत्पादन के रूप में संगणित नहीं किया जाएगा।

(4) खंड 1.7 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“1.8 प्रत्यय-पत्र के माध्यम से बिलों के संदाय के लिए 2.5 प्रतिशत की रिबेट अनुज्ञात की जाएगी। यदि संदाय, प्रत्यय-पत्र के माध्यम से भिन्न ढंग से किन्तु उत्पादक कंपनी द्वारा बिलों के प्रस्तुत किए जाने से एक मास की अवधि के भीतर किया जाता है तो उन पर एक प्रतिशत की रिबेट अनुज्ञात दी जाएगी।”

[फा० सं० 6/1/टैरिफ/96-वाल्थूम-IV-1]

एस० आर० शिवरेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1997

S.O. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43A of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power No. S.O. 251 (E), dated the 30th March, 1992, namely :—

In the said Notification.—

(1) in **Clause 1.2.**—after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided also that in case of multi-unit project, the percentage of capital cost as specified by the Authority in its techno-economic clearance shall be considered for fixation of tariff, on commercial operation of the progressive units but in case of delay in commissioning of second or subsequent units from the scheduled date, the project cost, for the period of delay, shall be retrospectively approved for the tariff purpose in the ratio of proportionate allocation of units ;

provided further that if the capital cost of the project increases, in comparison to the cost approved in Techno-economic-Clearance, on account of foreign exchange variation or change of law and approved by the competent Government ; the project developer may approach the Authority not more than once in year in any financial year for the mid term review of the capital cost".

(2) in **Clause 1.5,**

(A) in paragraph (c),

(i) for the words "Operations and Maintenance Expenses" the words "Operation and Maintenance Expenses including insurance" shall be substituted;

(ii) for the 'Note', the following 'Notes' shall be substituted, namely :-

"Note-1 The expenditure on the operation and maintenance including insurance, calculated on the basis of 2.5 per cent for the first year, shall be revised in each subsequent year as may be mutually agreed upon between the Board and the Generating Company on the basis of weighted price index. Alternately, the expenditure on operation and maintenance, calculated on the basis of 2 per cent for the first year, shall be revised in each subsequent year on the basis of weighted price index, but the actual expenditure on insurance or ceiling insurance expenses, for the first year shall not be subject to escalation in the subsequent year.

Note-2 In case of multi-unit project, the operation and maintenance expenses, in respect of each unit for the purpose of tariff, shall be allowed on the above percentage of the capital expenditure calculated in proportion to the capacity of each unit and not on the basis of allocation of capital expenditure in Techno-economic clearance. The escalation shall be allowed after one year, from the date of the commissioning of the units" ;

(B) in paragraph (d), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the tax on income on the business of electricity as a component of Annual Fixed Charge shall constitute the ceiling, but the Boards shall not invariably allow tax on income on incentive payable as a pass-through in tariff and shall negotiate for the tax on income not being a pass through beyond the generation level of 6000 hrs/kw/year"

(C) for paragraph (f), the following paragraph shall be substituted namely :-

"(f) Interest on Working Capital shall cover :

(i) Fuel cost for one month and reasonable fuel stocks as actually maintained but limited to fifteen days for pit head stations and thirty days for non pit head stations, calculated on normative plant load factor basis;

(ii) Sixty days stock of secondary fuel oil, calculated on normative plant load factor basis;

(iii) Operation and maintenance expenses (cash) for one month;

(iv) Maintenance spares at actuals subject to a maximum of one per cent of the capital cost but not exceeding one year's requirements less value of one fifth of initial spares already capitalised; and

- (v) Receivables equivalent to two months average billing for sale of electricity calculated on normative plant load factor basis";

(3) **for Clause 1.6,**—the following clause shall be substituted, namely :—

"1.6 Full fixed charges shall be recoverable at generation level of 6000/hours/kw/year (4500 hours/kw/year during stabilisation period). Payment of fixed charges below the level of 6000 hours/kw/years shall be on prorata basis. There shall not be any payment for fixed charges for generation level above 6000 hours /kw/year . For generation of above 6000 hours/kw/year, the additional incentive payable shall not exceed 0.7 per cent of paid up and subscribed capital, for each percentage point increase of Plant load factor above the normative level of 6000 hours/kw/year. While computing the level of generation, the extent of backing down, as ordered by the Regional Electricity Boards or State Load Despatch Centre, as the case may be, shall be reckoned as generation achieved. The payment of fixed charges shall be on monthly basis, proportionate to the electricity drawn by the respective Boards and other person. Necessary adjustment based on actual shall be made at the end of each year.

Note—1. The Additional incentive of return on equity of 0.7 per cent for each percentage increase above the normative level of 6000 hours/kw/year, mentioned above, shall be the maximum ceiling. It shall be open to the Generating Companies and Boards or other power purchasers to negotiate and fix a suitable lower additional incentive, within the above ceiling.

Note—2. For Naphtha based thermal plants, the extent of backing down, as ordered by Regional Electricity Boards or the State Load Despatch Centre, as the case may be, beyond plant Load factor of 6000 hours/kw/Year, shall not be reckoned as generation achieved for incentive purpose.

Note—3. For Diesel Engine generating units the extent of backing down, as ordered by Regional Electricity Boards or the State Load Despatch Centre, as the case may be beyond Plant Load factor operation norms laid down by the Central Electricity Authority for the time being, subject to modification therefore, if any, shall not be reckoned as generation achieved for incentive purpose";

4. **After clause 1.7,** the following clause shall be inserted, namely :—

- 1.8. For payment of bills through letter of credit, a rebate of 2.5 per cent. shall be allowed. If the payments are made by a mode other than through letter of credit but within a period of one month of presentation of bills by the Generating company, a rebate of 1 per cent shall be allowed."

[F. No. 6/1/Tariff/96/Vol.-IV-1]

S. R. SHIVRAIN, Jt. Secy.